LOK SABHA

Thursday, December 3, 1964/Agrahayana 12, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Speaker: Secretary may call out the name of the Member who has come to make and subscribe the oath or affirmation under the Constitution.

Secretary: Shri Madhu Ramchandra Limaye.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, I have great pleasure in introducing to you and through you to the House, Shri Madhu Ramchandra Limaye who has been declared elected to Lok Sabha from Monghyr constituency of Bihar in the vacancy caused by the death of Shri Banarsi Prasad Sinha.

Shri Madhu Ramchandra Limaye (Monghyr)

—

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Revolving Fund for Development of Land

\+

*326. Shri D. C. Sharma:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Daljit Singh:

Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Borooah:
Shri Oza:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Sivamurthi Swamy:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

(a) whether it has been decided to create a revolving fund for bulk acquisition and development of land in and around growing towns, where land prices are rising rapidly; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). Yes. The State Governments have been advised that the loans made available to them, both from the Life Insurance Corporation and the Government of India, should be pooled to serve as a revolving fund for bulk acquisition and development of land in and around growing towns. The Working Group on Housing and Urban and Rural Planning in the Fourth Plan has also recommended that 20 per cent of the funds earmarked for Housing in the Fourth Plan should be utilised for large scale acquisition and development of land.

Shri D. C. Sharma: May I know if it has been specified as to how much of this fund will be contributed by LIC and how much will be contributed by the State Governments?

Shri Mehr Chand Khanna: There is a total allocation of Rs. 180 crores for housing under the Third Plan. Out of this Rs. 60 crores is to come from the LIC and the remaining from the

Central Government under planned allocations.

Shri D. C. Sharma: May I know if this Revolving Fund which we are going to have for development of land near the towns will not be at the expense of rural housing; if so, may I know what steps Government are taking to see that the rural housing schemes succeed as before and that this scheme does not infringe upon the possibility of those schemes being successful?

Shri Mehr Chand Khanna: I do not think there should be any apprehension on that ground. We have different types of schemes, rural and urban, and allocation for rural housing is quite distinct from urban housing.

Shri D. N. Tiwary: May I know whether the State Governments have geared up their administrative machinery and are coming up to execute this scheme?

Shri Mehr Chand Khanna: I have recently taken up this matter with the State Governments. I have written to the Chief Ministers myself. I have told them that it would be very desirable that housing is under one minister. At the moment I find that in certain States housing is being handled by more than one minister. I have also suggested to the Chief Ministers that they should set up Housing Boards in their States because we are contemplating to set up a Central Housing Board at the Centre so that there is proper co-ordination.

श्री काशीराम गुप्त : क्या राज्य सरकारों को इस प्रकार के सभी आदेश दिए गए हैं कि इस फंड से जो जमीन खरीदी जाए उसमें प्राथमिकता उन योजनाओं को दी जाए जिनमें 200 रुपये से कम आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन मुहय्या करने की बात है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तो नही है । जो हम ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है वह यह है कि चूंकि जमीन का भाव बढ़ रहा है, इसलिए जितनी भी जमीन वह खरीद सकें खरीदें ताकि हमको अपने मकान बनाने में सुभीता हो और तकलीफ न हो । आज तक हमने इस काम के लिए राज्य सरकारों को 15 करोड़ रुपया दिया है और मेरा ख्याल है उन्होंने 11 या 12 हजार एकड़ के करीब जमीन एक्वायर की है ।

Shrimati Savitri Nigam: What is the shortfall in rural housing during the Third Plan? Is it a fact that rural housing programmes are going very slow?

Shri Mehr Chand Khanna: That has nothing to do with this question.

Shri S. N. Chaturvedi: May I know whether this fund will revolve clockwise or anti-clockwise *i.e.*, from bigger towns to smaller towns or from smaller towns to bigger towns?

Shri Mehr Chand Khanna: I have not been able to folloy the implication of clockwise and anti-clockwise.

Mr. Speaker: The clock moves towards the right. Perhaps he wants to know whether it will move to the left.

Shri P. C. Borooah: May I know how this fund will be administered in order to prevent misappropriation or misuse?

Shri Mehr Chand Khanna: I do not think there is any misappropriation or misuse.

Mr. Speaker: Should we start thinking of misappropriation even before the fund comes into existence?

श्री बड़े : अभी मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने राज्यों को पैसा दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने कितना पैसा दिया है और उस सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कितना पैसा दिया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मध्य प्रदेश सरकार का ताल्लुक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने टोटल 41 लाख 66 हजार रुपया लिया है और उन्होंने तकरीबन 524 एकड़ जमीन एक्वायर की है ।

श्री बागड़ी : यह जो शहरों के नजदीक की जमीन की कीमत बढ़ रही है उसके लिए यह फंड कायम किया गया है । सरकार और निगम ने गाजियाबाद वगैरह के किसानों की जमीनें थोड़ी कीमतों में ले ली हैं और उन को कई गुना कीमतों पर बेच रही है जिससे कि बाजार में फर्क पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और निगम कीमतों के बढ़ने पर रोक लगाने की सोच रहे हैं जिससे कि यह समस्या हल हो ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : शहरों की आबादी कुछ तो जाती तौर पर बढ़ रही है और कुछ बाहर से लोग वहां आ रहे हैं, इसलिए उन के लिए मकान बनाने जरूरी हैं । उसके लिए चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फरीदाबाद हो या गुड़गांवां हो, वहां की जमीन लेनी पड़ती है । बाकी जो हम मुआवजा देते हैं वह कवायद के मुताबिक देते हैं और जिस कीमत पर हम बेचते हैं वह भी कवायद के मुताबिक होती है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि आप जो ज्यादा कीमत लेते हैं वह न लें ताकि कीमतें न बढ़ें ।

श्री बागड़ी : क्या सरकार यह सोच रही है कि जो कीमत निगम और सरकार इन जमीनों की लेती है उस को कम करे....

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं ने कहा ।

श्री बागड़ी उसका उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : यही उत्तर है कि सरकार सोच रही है ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने जो जमीन किसान से ली 6 रुपए गज पर उसको कम्पनी और सोसाइटी बना कर 250 रुपए गज पर बेचा है । क्या यह समाजवादी सरकार यह सोच रही है कि उस जमीन के नीलाम से जो ज्यादा कीमत आयी है उसमें किसान को भी उसका हिस्सा दिलवाया जाए ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने कहा कि उस जमीन का कम्पेन्सेशन देने के बाद हम उस को डेवेलप करते हैं, उसके लिए बिजली लाते हैं, पानी लाते हैं, वहां सड़कें बनाते हैं । और फिर यह तो है नहीं कि एक गज जमीन ली है तो उस सारी जमीन पर मकान बना दिया जाएगा । उसमें से 30, 40 या 50 पर सेंट जमीन छोड़नी पड़ती है । इन तमाम चीजों को खयाल में रख कर कीमत मुकर्रर की जाती है । सरकार कोई मुनाफा नहीं कर रही है ।

भारतीय मुद्रा की कीमत

327. { **श्री बागड़ी** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 17 वर्षों से भारतीय मुद्रा की कीमत गिर रही है ;